नवसर्जन संस्कृति

TITLE CODE : UPHIN51496
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 221
दि. 12.12.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

राष्ट्रपति ने मणिपुर में नागरिक स्वागत समारोह में भाग लिया और इम्फाल में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया

■ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा- मणिपुर के युवा, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य इसे असीमित संभावनाओं वाला राज्य बनाते हैं

■ हमें मिलकर मणिपुर को एक ऐसे राज्य के रूप में मजबूत करना चाहिए जहां प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे, प्रत्येक महिला सशक्त महसूस करे, प्रत्येक समुदाय अपने को मुख्ं य धारा में माने और प्रत्येक नागरिक उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़े

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज शाम (11 दिसंबर, 2025) इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया।

अपने संबोधित में राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर लचीलेपन, साहस और असाधारण सांस्कृतिक समृद्धि की भूमि है। पीढ़ियों से, यहां के लोगों ने खेल, सशस्त्र बलों, कला और संस्कृति तथा सार्वजनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान देकर राष्ट्र को समृद्ध किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वे मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के बाद जनता

द्वारा झेले गए दर्द से अवगत हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मणिपुर की जनता की चिंताओं का ध्यान रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सद्भाव को मजबूत करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता एवं समृद्धि की राह पर मणिपुर का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार राज्य भर में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि विकास और प्रगति के लाभ राज्य के प्रत्येक कोने तक पहुंचें।

मणिपुर दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के जीवंत सम्बंधों का प्रवेश द्वार है। यहां की युवा पीढ़ी, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता इसे असीमित संभावनाओं वाला राज्य बनाती है। सशक्त महिलाएं मणिपुर की पहचान है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में मणिपुर की बहादुर महिलाओं द्वारा दो बार ऐतिहासिक नुपी लाल या महिला युद्ध लड़े गए। उन्होंने अपनी उचित मांगों को स्वीकार करने के लिए औपनिवेशिक और सामंती शक्तियों को बाध्य करने में सफलता प्राप्त की। वे प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर के लोग प्रतिभाशाली और मेहनती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग नए सिरे से सद्भाव बनाए रखेंगे और राज्य को समृद्धि और सुख की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

राष्ट्रपति ने मणिपुर की जनता से सद्भाव और विकास के उपायों का समर्थन जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर मणिपुर को एक ऐसे राज्य के रूप में मजबूत करना चाहिए जहां प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे, प्रत्येक महिला सशक्त महसूस करे, प्रत्येक समुदाय अपने को मुख्य धारा में माने और प्रत्येक नागरिक उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़े।

इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ऐतिहासिक मापाल कांगजेइबुंग में पोलो प्रदर्शनी मैच देखने भी पहुंची।

बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी का एक्शन मोड, घुसपैठियों पर वार, अधिकारियों को दो टूक, ढिलाई बर्दाश्त नहीं

(जीएनएस)।

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार शाम बरेली पहुंचे तो शहर से लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सर्किट हाउस में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में उन्होंने विकास योजनाओं की प्रगति की कड़ी समीक्षा की। सीएम का साफ संदेश था कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं, लक्ष्य समय पर और गुणवत्ता से पूरे होने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या किसी कीमत पर नहीं बचने चाहिए। जिले में संचालित संवेदनशील अभियानों पर फीडबैक लिया और पुलिस-प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। बांग्लादेशी और

रोहिंग्या जैसी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति कानून की पकड़ में आना चाहिए।

उन्होंने एसआईआर) की प्रगति भी परखी और कहा कि मतदाता सूची में किसी भी कीमत पर अपात्र व्यक्ति का नाम न रहने पाए। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी मंत्री जे.पी.एस. राठौर, वन राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, सांसद, मेयर, विधायक और भाजपा पदाधिकारी, एडीजी जोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री प्रणब मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने श्री मुखर्जी को एक महान राजनेता और असाधारण विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उन्होंने दशकों के सार्वजनिक जीवन में अटूट समर्पण के साथ देश की सेवा की। श्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहाः 'श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वह एक महान राजनेता और असाधारण विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे और उन्होंने दशकों के सार्वजनिक जीवन में अटूट समर्पण के साथ भारत की सेवा की। प्रणब बाबू की बुद्धिमत्ता और स्पष्ट विचार ने हर कदम पर हमारे लोकतंत्र को समृद्ध किया।

पुतिन के भारत दौरे के बाद पहली बार पीएम मोदी की ट्रंप से फोन पर हुई बात, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करते हुए द्विपक्षीय सहयोग के लगातार मजबूत होने पर संतोष व्यक्त किया।

आधिकारिक बयान के अनुसार, नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा और 21वीं सदी के भारत-अमेरिका कॉम्पैक्ट के तहत सहयोग विस्तार पर भी विचार किया।

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साक्षा की, जिसमें उन्होंने लिखा, " राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और साथ ही क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में साझा चुनौतियों का समाधान और समान हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी। रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने हेतु दोनों संपर्क में रहेंगे।

अमेरिका की संसद में पुतिन-मोदी की फोटो पर हंगामे के बाद ट्रंप ने की बात

बता दें, ट्रंप और पीएम मोदी की ये बातचीत रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत के दौरे की कारपूलिंग तस्वीर पर अमेरिका में छिड़ी बहस के तुरंत बाद हुई है। अमेरिकी कांग्रेस में भारत-अमेरिका संबंधों पर हुई चर्चा के दौरान प्रतिनिधि सिडनी कामलेगर-डव ने इस तस्वीर जिक्र करते हुए ट्रंप प्रशासन की भारत के प्रति अपनाई गई विदेश नीति पर सीधा हमला बोला था। सांसद डव ने कहा कि "यह फोटो हजार शब्दों के बराबर है। ट्रंप सरकार की भारत नीति को सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उन्होंने "अपनी नाक काटकर अपना ही नुकसान किया।" उनके अनुसार, ट्रंप की दबाव वाली कूटनीति ने भारत-अमेरिका संबंधों को कमजोर किया है, और मोदी-पुतिन की कारपूल फोटो इसी कूटनीतिक नुकसान को दिखाती है।"

ट्रंप और पीएम मोदी की ये बातचीत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च-स्तरीय दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आने के कुछ ही दिनों बाद हुई।

फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद यह पुतिन की भारत की पहली राजकीय यात्रा थी, जिसने वैश्विक ध्यान खींचा। बता दें व्यापक व्यापार तनाव और भारत द्वारा रूसी तेल आयात को लेकर चिंताओं के बीच, ट्रंप ने अगस्त 2025 में अधिकांश भारतीय निर्यातों पर 50% टैरिफ लगाया था।बाजार पहुँच और टैरिफ नीतियों पर विवादों के कारण, 10-11 दिसंबर को भारत आए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल की चचाओं में अब तक बहुत कम प्रगति हुई है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र जी की स्मृति में दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनका स्मरण कर उनकी स्मृतियों को नमन किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र जी की स्मृति में दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनका स्मरण कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 'धर्मेंद्र जी ने अपनी अभिनय कला से देशवासियों के दिलों में स्थान बनाया और उनकी अदाकारी भाषा व क्षेत्र की सीमाओं को पार कर जन-जन के मन में बस गई। भारतीय सिनेमा जगत को इस अद्वितीय अभिनेता की कमी हमेशा खलती रहेगी। आज दिल्ली में आयोजित उनकी श्रद्धांजलि सभा में उनका स्मरण कर उनकी स्मृतियों को नमन किया।

भारतीय नौसेना गोताखोरी में सहायक स्वदेशी निर्मितपहले जहाज 'डीएससी ए20' को कमीशन करेगी

भारतीय नौसेना 16 दिसंबर, 2025 को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के तत्वावधान में गोताखोरी में सहायक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहले जहाज 'डीएससी ए20' को अपनी सेवा में शामिल करेगी। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना की उपस्थिति में आयोजित होने वाला यह औपचारिक समारोह, नौसेना की परिचालन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक होगा। डीएससी ए20 का शामिल होना नौसेना के बेड़े के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है। इसके माध्यम से भारतीय नौसेना की गोताखोरी और जल के भीतर सहायता क्षमताओं में उल्लेखनीय तेजी आएगी।

फिक्की अन्नपूर्णा प्रदर्शनी 2025 ने भारत के विस्तारित खाद्य प्रसंस्करण इकोसिस्टम के द्वार खोले

● खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, किसानों और उपभोक्ताओं के लिए समृद्धि ला सकता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री अविनाश जोशी ने मुंबई में फिक्की अन्नपूर्णा प्रदर्शनी 2025 में यह बात कही

● भारत की खाद्य क्रांति फिक्की के अन्नपूर्णा इंटरफूड 2025 में केंद्रबिंदु बन गई है

(जीएनएस)।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव श्री अविनाश जोशी, आईएएस ने आज मुंबई में कहा, "एफआईसीसी का अन्नपूर्णा इंटरफूड कार्यक्रम भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कृषि, आजीविका और उपभोक्ता अनुभव को बदलने की क्षमता को दशार्ता है।"

श्री अविनाश जोशी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से फिक्की द्वारा आयोजित 17वीं अन्नपूर्णा इंटरफूड प्रदर्शनी में बोल रहे

थे। उन्होंने कहा, 'कृषि उत्पादकता में वृद्धि, घरेलू मांग में वृद्धि और उपभोग के बदलते स्वरूपों के साथ, हमें प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाना होगा, अन्यथा किसान अपनी समृद्धि से वंचित रह जाएंगे और उपभोक्ताओं को विकल्प, गुणवत्ता और निष्पक्षता से वंचित होना पड़ेगा। नीतिगत समर्थन, सब्सिडी और विश्वसनीय विनियमन के माध्यम से, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यह क्षेत्र सभी के लिए फले-फूले।ह्व

अन्नपूर्णा इंटरफूड कार्यक्रम में भारत, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के हितधारकों की एक बड़ी सभा आयोजित की गई। इसमें अग्रणी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, खरीदारों और व्यापार पेशेवरों की भागीदारी रही, जिसमें 17-18 देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के मजबूत बाजार के बारे में चर्चा की।

गांधीनगर में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू हुआ

● आणंद जिले के धुवारण में कार्यरत होगा केबल लैंडिंग स्टेशन प्रोजेक्ट

-: महात्मा मंदिर में वन टू वन बैठक आयोजित :-

● प्रोजेक्ट में 1317 करोड़ रुपए का संभावित निवेश होगा तथा 1300 से अधिक प्रत्यक्ष-परोक्ष रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे

● सीएलएस की स्थापना से डेटा सेंटर और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वृद्धि होगी

● गुजरात हाइपर स्केल और एंटरप्राइज डेटा सेंटर के लिए पसंदीदा स्थान बनेगा

● राज्य सरकार-गिफ्ट सिटी और हेनोक्स आईटी एंड डेटा सेंटर्स के बीच एमओयू

गांधीनगर, 11 दिसंबर : गुजरात में डेटा सेंटर और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में वृद्धि कर हाइपर स्केल और एंटरप्राइज डेटा सेंटर के लिए गुजरात को डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में इस उद्देश्य से गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राज्य सरकार, गिफ्ट सिटी और शारजाह की हेनोक्स आईटी एंड डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू किया गया।

यह डेटा केबल लैंडिंग स्टेशन प्रोजेक्ट लगभग 1317 करोड़ रुपए के संभावित निवेश के साथ आणंद जिले के धुवारण में आकार लेगा और प्रत्यक्ष-परोक्ष मिलाकर 1300 से अधिक रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

गांधीनगर में आयोजित हो रही रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए हेनोक्स आईटी के सीईओ मसूद एम. शरीफ महमूद तथा शारजाह कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजीस ऑथोरिटी (एससीटीए) के कार्यपालक निदेशक श्री राशिद अल- अली एवं यूएई के भारत स्थित राजदूत डॉ. अब्दुल नासिर जमाल अलशाली ने यह एमओयू करने के बाद मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात बैठक आयोजित की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सीएलएस प्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप आने वाले दिनों में गुजरात में तेज और मजबूत अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी से एआई, मशीन लर्निंग, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म और जीसीसी के विकास को गति मिलेगी।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

पश्चिम रेलवे चलाएगी उर्स उत्सव के दौरान बांद्रा टर्मिनस और अजमेर के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर उर्स उत्सव के दौरान यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान रखते हुए बांद्रा टर्मिनसझअजमेर स्टेशन के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेन चलायी जाएगी। इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09063/09064 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09063 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल बुधवार, 24 दिसंबर, 2025 को 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06:15 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09064 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 को 11:40 बजे अजमेर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, नडियाद, साबरमती, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिण्डवाड़ा, फालना, रानी, मारवाड़, सोजत रोड और ब्यावर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में अउ - 2 टियर, अउ - 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09063 के लिए बुकिंग 12 दिसंबर 2025 से सभी ढफर काउंटरों और क्मळळउ वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बनासकाँठा को 1004 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट दी

गांधीनगर, 11 दिसंबर :बनासकाँठा जिले में शुक्रवार को विकास का महापर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास कर जिलावासियों को भव्य भेंट दी।

श्री पटेल ने बनासकाँठा के 7 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 15 से अधिक बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ वाव-थराद-बनासकाँठा जिले में नोबेल प्राइज एग्जीबिशन का भी उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी बच्चों में विज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षा के प्रति उत्साह जागृत करेगी। मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान से 'सशक्त नारी मेला' का प्रारंभ किया और स्वयं-सहायता समूहों की बहनों के साथ संवाद भी किया। शुक्रवार से शुरू हुए ये राज्यव्यापी स्वदेशी मेले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन' अभियान को और गति देंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की राजनीति से सर्वांगीण विकास किया है। उनकी विजनरी लीडरशिप का जो लाभ ढाई दशक से राज्य को मिला है, उसमें अनेक मील के पत्थर पार हुए हैं। उनके दिशादर्शन में गुजरात दिन-प्रतिदिन तेजी से प्रगति कर रहा है।

श्री पटेल ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क

गुजरात में बन रहा है। एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सिटी धोलेरा में डेवलप हो रही है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 'सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे' गुजरात से शुरू होता है। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र गिफ्ट सिटी-गुजरात में है। देश की प्रथम बुलेट ट्रेन भी गुजरात से शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि मोदी साहब के नेतृत्व के चलते कल ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने दीपावली के पर्व को अमूर्त धरोहर के रूप में घोषित किया है, तो इससे पहले हमारा गरबा भी यह गौरव प्राप्त कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नौ संकल्पों के माध्यम से हम राष्ट्रप्रेम तथा देश के लिए कुछ करने की भावना जागृत करें। 'कैच द रेन', 'एक पेड़ माँ के नाम', 'स्वच्छता' जैसे अभियानों को हम अपनी आदत बनाएँ। प्राकृतिक खेती तथा गाय आधारित खेती अपनाएँ और स्वस्थ जीवनशैली के लिए योग एवं खेल-कूद को जीवन का हिस्सा बनाएँ।

उन्होंने स्वदेशी मेलों के गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वदेशी को प्रोत्साहन देने के प्रेरक बल बनने की भूमिका देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 का लक्ष्य रखा है, जिसमें गुजरात भी आत्मनिर्भर एवं विकसित गुजरात से योगदान देने के लिए सज्ज है।

इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने कहा कि वर्षों की समस्या का निवारण आया है। बनासकाँठा को बहुत बड़ी भेंट मिली है। उन्होंने इस भेंट के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया। श्री चौधरी ने कहा कि सूखे-वीरान बनासकाँठा में नर्मदा की नहर लाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बनासकाँठा को हरियाला बनाते हुए विकास की शुरूआत की थी, जिसे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे बढ़ाते हुए करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइनें डालकर बनासकाँठा के तालाब भरने का कार्य किया है। जिले को पानी की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का राज्य सरकार ने दृढ़ आयोजन किया है।

कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया, बनासकाँठा जिला प्रभारी मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल, मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी, मंत्री श्री संजयसिंह महिडा, मंत्री श्री स्वरूपजी ठाकोर, विधायक श्री अनिकेत ठाकर, विधायक श्री लविंगजी ठाकोर, जिला कलेक्टर श्री मिहिर पटेल, जिला विकास अधिकारी श्री एम. जे. दवे, जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत सुंबे सहित अधिकारी तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन-भावनगर मंडल द्वारा निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं का भव्य सम्मान समारोह आयोजित

(जीएनएस)।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन-भावनगर मंडल द्वारा रेलवे कर्मचारियों के आश्रित बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित निबंध लेखन तथा चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करने हेतु दिनांक 11 दिसंबर, 2025 (गुरूवार) को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विजेताओं को प्रमाण-पत्र व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम रेलवे ऑफिसर्स क्लब, भावनगर परा में संपन्न हुआ।

महिला कल्याण संगठन द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 14 सितम्बर 2025 को तथा चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन

21 सितम्बर 2025 को किया गया था। इन दोनों प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित विजेता प्रतिभागियों को संगठन की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा द्वारा सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान भावनगर मंडल सांस्कृतिक संघ के सदस्यों तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, भावनगर रेलवे मंडल के सदस्यों को भी उनके योगदान एवं सक्रिय सहभागिता हेतु संगठन की अध्यक्षा द्वारा सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह में विजेता प्रतिभागी अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिला कल्याण संगठन-भावनगर मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती मोनिका शर्मा, सेक्रेटरी श्रीमती माया त्रिपाठी, ट्रेजरर श्रीमती वंदना पाटीदार, कल्चरर इंचार्ज श्रीमती रश्मि मलिक, कैटरिंग इंचार्ज श्रीमती शिखा राणा तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहीं।

महिला कल्याण संगठन-भावनगर मंडल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करता है, बल्कि उन्हें प्रेरित कर उनके बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के तहत 13 दिसंबर तक करें आवेदन : डीसी

सुशासन दिवस पर राज्य व जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व टीम को किया जाएगा पुरस्कृत

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आगामी 25 दिसंबर 2025 को साल 2024-2025 में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 'गुड गवर्नेंस अवॉर्ड' दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के अंतर्गत उन अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत कर शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, जिनके अभिनव, अभ्यास और असाधारण प्रयास पूरे राज्य में बेहतर शासन में योगदान करते हैं।

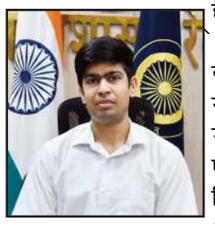

डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम, सोसाइटी, विश्वविद्यालय, हरियाणा सरकार के अधीन उपक्रम के सभी पात्र कर्मचारी (रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट वाले) अपने-अपने ऑफिस-हेड या विभागाध्यक्ष या संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के जरिए ऑनलाइन पोर्टले पर 13 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट/स्कीम/प्रोग्राम का चयन करने उपरांत नॉमिनेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, विभागाध्यक्ष और आईएएस ऑफिसर को इनमें शामिल नहीं किया गया है।

डीसी ने बताया कि सभी इच्छुक अधिकारियों/अधिकारियों या कर्मचारियों की टीम, जिन्होंने बहुत अच्छा और इनोवेटिव काम किया है, वे अपने आवेदन विभागाध्यक्ष/विभाग के कार्यालय/संगठन को भेज सकते हैं, जिनकी उनके द्वारा जांच की जाएगी और अपनी सिफारिशों के साथ आगे भेजी जाएगी। स्टेट अवॉर्ड सभी कर्मचारियों के लिए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए खुला है, जो स्टेट लेवल पर दिए जाएंगे और हर जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट-लेवल अवॉर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिए जाएंगे। कोई भी डिपार्टमेंट अपने-अपने डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा स्कीम के लिए कर्मचारी का नाम प्रस्तावित कर सकता है। उन्होंने बताया कि सभी विजेताओं को एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर किया हुआ अवॉर्ड सर्टिफिकेट और नकद इनाम दिया जाएगा। इससे संबंधित विस्तार से जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

विकासखंड तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में मनरेगा का बड़ा फजीर्वाड़ा उजागर

मजदूरों के हक पर डाका — ऑनलाइन अटेंडेंस में संख्या बड़ी, जमीन पर नदारद मजदूर

(जीएनएस)। बलरामपुर

विकासखंड तुलसीपुर से मिली सूत्रों की विश्वसनीय जानकारी के अनुसार मनरेगा योजनाओं में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। जितनी ऑनलाइन अटेंडेंस दिखाई जाती है, उतने मजदूर मौके पर काम करते नहीं मिलते। मीडिया की टीम जब विभिन्न कार्यस्थलों पर पहुंची तो कहीं कुछ मजदूर मिले, तो कहीं एक भी श्रमिक मौजूद नहीं था। यह स्थिति न केवल सरकारी धन की खुली लूट को दशार्ती है, बल्कि गरीब मजदूरों के हक पर सीधे डाका डालने जैसा है।

ग्राम पंचायत महादेया में मास्टर रोल पर 57 मजदूरों की ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज है, लेकिन मौके पर मात्र 12 मजदूर ही काम करते मिले। बाकी मजदूरों का रिकॉर्ड केवल कागजों और ऑनलाइन सिस्टम तक ही सीमित मिला।

ग्राम पंचायत गोपालपुर में स्थिति और भी चौंकाने वाली रही। यहां मास्टर रोल में 78 मजदूरों

की उपस्थिति दिखाई गई थी, जबकि वास्तविकता में सिर्फ 20 मजदूर कार्यस्थल पर मौजूद पाए गए। यह सीधे तौर पर अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

ग्राम पंचायत सुगा नगर में फजीर्वाड़ा चरम पर मिला। दो मास्टर रोल में 30 मजदूरों की ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज थी, लेकिन जांच टीम को मौके पर एक भी मजदूर नहीं मिला। यह मनरेगा धन के दुरुपयोग का सबसे बड़ा प्रमाण बनकर सामने आया।

ग्राम पंचायत महादेव हरिहर नगर में चार मास्टर रोल पर 32 मजदूरों की ऑनलाइन अटेंडेंस दिखाई गई है, परंतु वास्तविक संख्या कितनी है, यह भी जांच के घेरे में है।

इन खुलासों ने विकासखंड तुलसीपुर में मनरेगा कार्यों की सच्चाई को सामने ला दिया है। यह स्पष्ट है कि कागजों और ऑनलाइन सिस्टम में मजदूरों की संख्या बढ़ाकर सरकारी पैसा निकाला जा रहा है, जबकि मजदूरों को उनका वास्तविक हक नहीं मिल पा रहा। संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिनकी निगरानी की कमी से यह फजीर्वाड़ा फल-फूल रहा है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब मजदूरों को उनका सही हक मिल सके और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बहाल हो सके।

जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

समाधान शिविर में मौके पर ही बनाई पेंशन, सरकार का किया धन्यवाद

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की पहल पर जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय सहित उपमंडल स्तर पर लगाए जा रहे समाधान शिविर आमजन की शिकायतों का समाधान करवाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। समाधान शिविर में नागरिकों को एक ही स्थान पर अपनी शिकायतों व समस्याओं का समाधान करवाने का अवसर मिल रहा है। डीसी अभिषेक मीणा ने गुरुवार को जिला सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता करते हुए जन शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवाकर आमजन को राहत पहुंचाई।

डीसी अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर में मौके पर ही कंवाली निवासी नरेश कुमार की अविवाहित पेंशन बनवाई, जिस पर नरेश कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाधान शिविर में लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाता है, जिससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इसके अलावा गांव भाड़ावास में खेत के रास्ते से मिट्टी उठाने पर डीसी ने खनन अधिकारी को जांच करते हुए जुमार्ना लगाने के निर्देश दिए। गांव जैतड़ावास में रास्ते पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत पर डीसी ने डीडीपीओ को अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। गांव डहीना में

पंचायती रास्ते की पैमाइश करवाने के लिए संबंधित नायब तहसीलदार को निर्देश दिए। सेक्टर-3 सीवरेज चैंबर व नाले की साफ-सफाई करवाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए। कालाका रोड पर वार्ड नंबर 6 में गली कौ मिट्टी से लेवलिंग करने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए। समाधान शिविर में नागरिकों द्वारा मुख्य रूप से फैमिली आईडी में सदस्य जोडने. से संबंधित, राशन कार्ड, पुलिस विभाग, बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवा दिया गया। वहीं शेष बची शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

डीसी ने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारी आमजन की शिकायतों के निवारण की दिशा में तत्परता से कार्रवाई कर उन्हें राहत पहुंचाए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय में जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन नागरिकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं और जनहित में यह पहल निरंतर जारी रहेगी।

इस अवसर पर एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम रेवाड़ी सुरेश कुमार, भाजपा नेता हुकमचंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा आमजन की समस्याओं/शिकायतों की जनसुनवाई

त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

(जीएनएस)। बलरामपुर

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बलरामपुर में जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए शिकायतकताओं/आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा प्रत्येक प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

प्रत्येक मामले में संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे समयबद्ध, प्रभावी एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

राजस्व संबंधी मामलों में त्वरित समाधान हेतु पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर, संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर, गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण के निर्देश प्रदान किए गए।

यह जनसुनवाई कार्यक्रम आम जन की समस्याओं के निराकरण में पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचायक है।

श्री पीयूष गोयल ने पारदर्शिता बढ़ाने, उद्योग-सरकार सहयोग और दक्षता में सुधार का आह्वान किया

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड) में एनईएसटी-02 (न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टावर-चरण 2) का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई के सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड) में एनईएसटी-02 (न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टावर-चरण 2) का उद्घाटन किया और उद्योगों से भारत की भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल विकास पहलों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करने का आग्रह किया।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई विकास की गति को एसईईपीजेड में भी बरकरार रखा जाना चाहिए और कहा कि क्षेत्र को अपने कार्यप्रणाली और प्रदर्शन को राष्ट्र की व्यापक आर्थिक गति के अनुरूप बनाना होगा।

श्री गोयल ने एसईईपीजेड इकाइयों को प्रशिक्षण प्रयासों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें विशेष रूप से सक्षम युवाओं के लिए पहल भी शामिल है और कहा कि कौशल विकास भारत के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योग जगत से कार्यबल विकास में सहयोग देने और व्यापक राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंडा में योगदान देने में अधिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया।

मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के शासन दृष्टिकोण के केंद्र में बनी हुई हैं। उन्होंने इकाई धारकों और उद्योग प्रतिनिधियों से प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसईईपीजेड स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित हो, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे वातावरण को बनाए रखना एक साझा जिम्मेदारी है।

श्री गोयल ने कहा कि स्थान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए नीलामी आधारित आवंटन और पारदर्शी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। उन्होंने हितधारकों को सामूहिक रूप से अप्रयुक्त भूखंडों की समीक्षा करने और निर्यात क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाने हेतु प्रबंध समिति के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनुमोदन, सीमा शुल्क संचालन, रखरखाव अनुबंध और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

मंत्री ने एसईईपीजेड में चल रहे और नियोजित बुनियादी ढांचा उन्नयन की समीक्षा की, जिसमें आंतरिक सड़कों, हरियाली और पूरे क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में सुधार शामिल हैं।

नगर निकायों में जनसुविधाओं के उन्नयन के लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक संपन्न, मा० चेयरमैनगण रहें उपस्थित

बैठक में नगर निकायों को स्वच्छ एवं सुंदर किए जाने हेतु वॉल पेंटिंग , रोप लाइट के साथ साथ बनाए वेंडिंग जोन नगर पालिकाए एवं नगर पंचायतें हो अतिक्रमणमुक्त - डीएम

(जीएनएस)। बलरामपुर

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में नगर निकायों की जनसुविधाओं एवं सुंदरीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं आगे की कार्ययोजना को लेकर विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के मा० चेयरमैनगण, अधिशासी अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण व यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना प्राथमिकता है। इस क्रम में सभी नगर

निकायों में मुख्य मार्गों, चौराहों एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर आकर्षक वॉल पेंटिंग, थीम-आधारित रोप लाइट, लैंडस्केपिंग किए जाएँ। उन्होंने कहा कि यह कार्य न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएंगे बल्कि जनजागरूकता को भी बढ़ावा देंगे।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक नगर निकाय में वेंडिंग जोन चिह्नित कर विकसित किए जाएँ। उन्होंने कहा कि वेंडिंग जोन से सड़क किनारे अनियमित रूप से लगने वाली दुकानों पर रोक लगेगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रहेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नगर पालिकाएँ एवं नगर पंचायतें अपने क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त रखें। इसके लिए नियमित अभियान चलाया जाए, साथ ही ऐसे स्थानों को चिन्हित कर स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जाए जहाँ बार-बार अतिक्रमण होता है।

बैठक में नगर निकायों के चेयरमैनगण द्वारा विभिन्न स्थानीय समस्याएँ एवं सुझाव भी प्रस्तुत किए गए, जिन पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि नगर निकायों के विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा सभी योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए।

बैठक में मा० चेयरमैन नगर पालिका बलरामपुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, चेयरमैन नगर पालिका उतरौला, चेयरमैन नगर पंचायत पचपेड़वा, गैंसडी , चेयरमैन प्रतिनिधि तुलसीपुर , एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योति राय , समस्त अधिशाषी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

एसआईआर की समयसीमा वृद्धि

एसआईआर की निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाकर न सिर्प एसआईआर में शामिल होने वाले नागरिकों को राहत दी है बल्कि इस कार्यव्रम में कार्यरत लाखों उन कर्मियों को राहत दी है जो दिन-रात एक करके डेटा संग्राह एवं जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। दरअसल यह कार्य बेहद संवेदनशील है। जिन लोगों को बीएलओ यानि बूथ लेवल आफिसर बनाया गया है, उन्हें वुछ क्षेत्रों में धमकियां तब मिल रही हैं जब वे सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं। यदि जल्दबाजी में सूचनाओं की समीक्षा में गलती हो जाए, तब तो फिर महाभारत होना तय है। असल में चुनाव आयोग ने उन राज्यों में समय-सीमा बढ़ दी है जहां जल्दी चुनाव नहीं हैं किन्तु जिन राज्यों में चुनाव अगले वर्ष है, वहां पर समय सीमा नहीं बढ़ाई है। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष 2026 में ही चुनाव होना है किन्तु वहां पर एसआईआर की प्रव्रिया के लिए समय-सीमा बिल्वुल नहीं बढ़ाई गई है। यह सच है कि जिन लोगों के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं, उनका न सिर्प मतदाता सूची से नाम कट जाएगा बल्कि उनमें से काफी लोगों की नागरिकता भी खतरे में पड़ जाएगी। यही है कि जो लोग दूसरे देशों से आकर भारत में बसे हैं भले ही वे वर्षो से यहां रह रहे हों किन्तु यदि उन्होंने औपचारिक तरीके से नागरिकता ग्राहण नहीं की है तो उनको डिटेंशन सेंटर में जाने का डर सता रहा होगा। सच तो यह है कि एसआईआर के पीछे-पीछे एनआरसी भी आने वाली है। मतलब यदि वोटर लिस्ट से नाम कटा तो पहले डिटेंशन सेंटर फिर एनआरसी पूरा होते ही सीएए की औपचारिकता पूरी होनी है। विपक्ष में जो पार्टियां दूसरे देशों के अवैध घुसपैठियों के बल पर चुनाव में वोट बटोरते रहे हैं, उनका यह कहना सच है कि अभी तो काफी वोटर डिटेंशन के डर से भाग रहे हैं। बाकी जो बचेंगे वह एनआरसी के शिकार होंगे। सरकार चाहती भी यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार कोई भी हो वह किसी देश के अवैध प्रवासियों को स्वीकार वैसे कर सकती है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर प्रतिवूल टिप्पणी करते हुए उन्हें बाहर निकालने का समर्थन कर चुका है। बहरहाल एसआईआर में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही असामान्य कार्य हो रहा है। यदि जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त अवसर नहीं मिला तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा हर राज्य में अलग तिथियों तक एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त करने का फैसला बिल्वुल सही है। इस प्रक्रिया के तहत यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो सभी पार्टियों का कर्तव्य है कि सब लोग उक्त पीड़ित को न्याय के लिए संरक्षण दें। किन्तु यह कहना कि समूची एसआईआर प्रक्रिया ही गलत है, यह उचित नहीं है। लब्बोलुआब यह है कि वर्षो से हमारी प्रवृत्ति रही है कि कौन पूछता है, इसलिए आज इतने घुसपैठिये देश के अलग- अलग राज्यों में फैले हैं। यदि शुरू से ही बीच-बीच में गहन जांच होती रहती तो आज यह नौबत न आती।

प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में एआई राष्ट्रीय प्रगति का मिशन बना है : मुख्यमंत्री

■ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने महात्मा मंदिर में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराया

■ उप मुख्यमंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की उपस्थिति

■ जन सुख-समृद्धि में वृद्धि, पारदर्शिता तथा फ्यूचर रेडी गुजरात के लिए एआई सक्षम संसाधन है : मुख्यमंत्री

■ मुख्यमंत्री ने गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक को ऑपरेशनलाइज्ड कर डिजिटल गवर्नेंस को अधिक स्मार्ट, तेज तथा सिटीजन सेंट्रिक बनाने की मंशा व्यक्त की

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

● गुजरात ने टेक्नोलॉजी प्रेरित विकास में सदैव अग्रसरता बनाए रखी है

● एग्रीकल्चर, हेल्थ, गवर्नेंस, अर्बन-रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पर चिंतन-मंथन विकसित गुजरात@2047 के विजन में नया बल देगा

-: उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी :-

● एआई केवल एक क्षेत्र नहीं; बल्कि नई ऊर्जा है, जो प्रत्येक क्षेत्र को गति के साथ शक्ति दे रही है, गुजरात एआई क्रांति का केन्द्र बनेगा

● निवेशकों तथा एआई स्टार्टअप्स के लिए गुजरात प्लेटफॉर्म बनेगा, उज्वल भविष्य के लिए लॉन्च पैड बनेगा

■ 'सुशासन' के लिए वर्तमान समय में एआई सबसे शक्तिशाली टूल्स के रूप में स्थापित : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया

■ मुख्यमंत्री के करकमलों से 'गुजरात एआई स्टैक' की लॉन्चिंग तथा 'गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइन्स 2025' का अनावरण किया गया

■ गुजरात सरकार ने गूगल, भाषिणी, गिफ्ट सिटी तथा हेनोक्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

गांधीनगर, 11 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यव्यापी गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक को ऑपरेशनलाइज कर डिजिटल गवर्नेंस को अधिक स्मार्ट, तेज तथा सिटीजन सेंट्रिक बनाने की मंशा व्यक्त की है।

उन्होंने जोड़ा कि इसके परिणामस्वरूप नागरिकों को सभी सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म से आसानी से मिलने के साथ विभागों के बीच डेटा शेयरिंग तेज बनने से योजनाओं के आउटकम का रीयल टाइम एनालिसिस भी हो सकेगा।

श्री पटेल गुरुवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित हो रही रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस अंतर्गत आयोजित एआई एक्सपीरियंस जोन का उद्घाटन कर विभिन्न स्टार्टअप स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया उपस्थित रहे।

इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केन्द्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपक्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में फरवरी-2026 में आयोजित होने वाली एआई इम्पैक्ट समिट के पूर्वार्ध तथा प्री-इवेंट के रूप में किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर गुजरात एआई स्टैक लॉन्च किया। इस एआई स्टैक के लॉन्च होने से सरकारी विभागों में 'प्लग-एंड-प्ले' एआई अपनाने के लिए 6 प्रमुख एआई टूल्स-कृषि एआई, योजना की पात्रता जाँच, प्रोक्योरमेंट चैटबोट, ग्रीवेंस क्लासीफायर, डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रैक्टर तथा चैट मैनेजमेंट टूल से गवर्नेंस

अधिक तेज, सटीक तथा नागरिकोन्मुखी बनेगा।

गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइन्स 2025 भी महानुभावों ने लॉन्च की। राज्य के डिजिटल गवर्नेंस को अधिक सुरक्षित, स्केलेबल तथा एआई रेडी बनाने के लिए ये गाइडलाइन्स 2025 में उपयोगी सिद्ध होंगी और टी३८एम्पैनल्ड कम्प्यूट का उपयोग आसान बनेगा।

इस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें गुजरात सरकार – गूगल और भाषिणी के बीच हुए एमओयू के अनुसार बहुभाषीय एआई, गुजराती भाषा मॉडलों और डिजिटल पब्लिक सर्विसेज के लिए रणनीतिक भागीदारी की जाएगी।

इतना ही नहीं; गुजरात सरकार-गिफ्ट सिटी तथा हेनोक्स द्वारा राज्य में केबल लैंडिंग स्टेशन्स (सीएलएस) स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया। इससे गुजरात वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी का केन्द्र बनेगा तथा ग्रीन डेटा सेंटर्स को बल प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप में एआई केवल टेक्नोलॉजी का संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का मिशन बन गया है। गुजरात ने सदैव टेक्नोलॉजी प्रेरित विकास में अग्रसरता बनाए रखी है। उन्होंने जोड़ा कि जन सुख-समृद्धि में वृद्धि, पारदर्शिता तथा फ्यूचर रेडी गुजरात के लिए एआई सक्षम संसाधन है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में देश में गत एक दशक में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति तक टेक्नोलॉजी पहुँची है और इंडिया एआई मिशन शुरू हुआ है। गुजरात ने भी इसके अनुरूप रहकर टास्क फोर्स का गठन किया है।

उन्होंने अपेक्षा दर्शाई कि इस रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में होने वाला सामूहिक मंथन एआई के उपयोग द्वारा टेक्नोलॉजी की मदद से आज के कार्यों से आने वाले कल की क्षमता के दृष्टिकोण को बदलने में उपयोगी बनेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गुजरात को एआई क्रांति का निर्माण करने वाला राज्य बताया और निवेशकों तथा एआई स्टार्टअप्स का गुजरात में स्वागत किया।

श्री संघवी ने कहा कि गुजरात सदैव 'अतिथि' तथा 'इनोवेशन'-इन दो शक्तिशाली परिबलों का स्वागत करता आया है। हमारा लक्ष्य 'मन वर्सेज मशीन नहीं, बल्कि 'मन विद मशीन है, जहाँ मानव कल्पना ने एक ऐसे पार्टनर का निर्माण किया है, जो कल्पना भी कर सकता है। एआई अब केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि नई ऊर्जा है, जो प्रत्येक क्षेत्र को गति के साथ शक्ति दे रही है।

उन्होंने गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे एआई आधारित उपयोगों पर प्रकाश डालते हुए जोड़ा कि गिफ्ट सिटी में माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्थापित एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) भारत के आगामी टेक इकोसिस्टम को आकार दे रहा है। यह हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में गति दे रहा है। गुजरात में कृषि क्षेत्र में फसल एआई प्लेटफॉर्म द्वारा किसानों को पानी की बचत करने तथा कीटाणुनाशकों का उपयोग कम करने में मदद मिल रही है। कृषि प्रगति प्लेटफॉर्म पर एक लाख से अधिक किसानों को फसल के स्वास्थ्य, भूमि की स्थिति तथा जल की उपलब्धता के बारे में एआई आधारित सलाह मिल रही है, जो उनकी आय बढ़ाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त; सिम्बा-एसआईएमबीए प्रोजेक्ट द्वारा वन्यजीवों की रक्षा की जा रही है। सार्वजनिक परिवहन सेवा जीएसआरटीसी में भी कार्यक्षमता सुधारने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है।

श्री संघवी ने गुजरात पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए एआई टेक्नोलॉजी के किए गए उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अहमदाबाद में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथजी की रथयात्रा में पुलिस ने एआई सर्वेलांस के जरिए 5,481 गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनका परिवार से पुनर्मिलन कराया। इतना ही नहीं, सुदूरवर्ती तथा ट्राइबल क्षेत्र माने जाने वाले दाहोद जिले में पुलिस ने अवैध गांजे की खेती के विरुद्ध राज्य का पहला एआई आधारित ऑपरेशन चलाया। मशीन-लर्निंग मॉडलों ने गांजे के पौधों को पहचाना और ड्रोन सर्वेलांस से 1.19 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का गांजा पकड़ा। इसके अलावा, अंबाजी मेले में एआई सर्वेलांस ने संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर गुमशुदा व्यक्तियों को खोजा तथा भीड़ प्रबंधन को मजबूत बनाया।

श्री हर्ष संघवी ने सभी निवेशकों और एआई स्टार्टअप्स को गुजरात में निवेश करने, निर्माण करने तथा अपने सपने साकार करने के लिए आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, 'गुजरात आपका प्लेटफॉर्म बनेगा। गुजरात आपके भविष्य का लॉन्च पैड बनेगा।ह्व

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि सुशासन के लिए वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई सबसे शक्तिशाली टूल्स के रूप में स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात एआई क्षेत्र में अग्रसर रहा है। एआई के माध्यम से टेक्नोलॉजी, डेटा स्टोरेज, दैनिक कार्य में तेजी और पारदर्शिता आई है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को घर बैठे सुविधा देने सहित विभिन्न सेवाओं में बड़ा परिवर्तन आया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत एआई तकनीक में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। पुरानी और नई पीढ़ी रेडियो, टीवी, कंप्यूटर और अब एआई तकनीक क्षेत्र में आने वाले बदलाव की साक्षी बनी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात में आयोजित यह 'रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस' भविष्य में एआई क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी।

टी३ के अपर सचिव और एनआईसी के महानिदेशक श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशानिर्देशन में भारत में आगामी फरवरी 2026 में 'एआई इम्पैक्ट समिट' आयोजित होगी। विश्व में पहली बार किसी विकासशील देश में वैश्विक स्तर की एआई समिट आयोजित होगी। इस समिट को अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य में भी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आह्वान किया था, जिसके परिणामस्वरूप आज यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन में गुजरात हमेशा देश में लीड लेकर अग्रसर रहा है। अब एआई के क्षेत्र में भी गुजरात देश के लिए रोल मॉडल बनेगा।

इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती ने स्वागत संबोधन में एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न थीमैटिक सत्रों की विस्तृत भूमिका देते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एआई फॉर एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, गवर्नेंस, अर्बन- रूरल ट्रांसफॉर्मेशन और फिन-टेक जैसे पाँच विषयों पर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी तथा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 'एआई इम्पैक्ट समिट' के लिए मूल्यवान सिफारिशें भी की जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में गुजरात इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अरविंद विजयन ने आभार व्यक्त किया।

रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि, गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक श्री संजय कौल, शारजाह कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजीस ऑथोरिटी के कार्यपालक निदेशक श्री राशिद अली अल-अली, गुजकोस्ट के सलाहकार श्री नरोत्तम साहू, भारत और गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैश्विक टेक कंपनियाँ, आईआईटी, उद्योग जगत के विशेषज्ञ तथा 100 से अधिक स्टार्टअप्स से जुड़े इनोवेटर्स उपस्थित रहे ।

भारतीय रेल ने 812 मेगावाट सौर ऊर्जा और 93 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करके नवीकरणीय ऊर्जा को गति दी

भारतीय रेल ने 812 मेगावाट सौर ऊर्जा और 93 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करके प्रचालन क्षमता बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को गति दी; 1,600 मेगावाट की चौबीसों घंटे चलने वाली हाइब्रिड बिजली परियोजना के लिए भी समझौता किया

भारतीय रेल ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया, सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति जारी

ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2 प्रतिशत हिस्सा पहले ही विद्युतीकृत; 2014 से अब तक रूट विद्युतीकरण दोगुने से भी अधिक हुआ जो छह दशकों में 21,801 किमी से बढ़कर 2014-25 के बीच 46,900 किमी तक पहुंचा

(जीएनएस)।

भारतीय रेल सुरक्षा, समयबद्धता, विश्वसनीयता और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकीयों के अंगीकरण के साथ अपनी अवसंरचना और रेलगाड़ियों का निरंतर उन्नयन कर रहा है। ये उन्नयन प्रणाली के आधुनिकीकरण और यात्रियों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों को दशार्ते हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने और रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ, कोयला आधारित इंजनों और डीजल इंजनों के उपयोग में कमी आई है।

भारतीय रेल में रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में शुरू किया गया है। अब तक, ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.2 प्रतिशत विद्युतीकृत हो चुका है। शेष नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य जारी है। 2014-25 के दौरान और 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण का विवरण इस प्रकार है:

अवधि-मार्ग किमी-2014 से पहले (लगभग 60 वर्ष) 21,801, 2014-25, 46,900

भारतीय रेल अत्याधुनिक तीन-चरण आईजीबीटी प्रौद्योगिकी आधारित लोकोमोटिव का विनिर्माण और कमीशनिंग कर रही है। इन लोकोमोटिव में रिजेनेरेटिव विशेषताएं हैं जिसके कारण ये ब्रेकिंग के दौरान खपत होने वाली ऊर्जा के एक हिस्से को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम हैं और इस प्रकार अधिक ऊर्जा कुशल हैं।

कोयले से चलने वाले इन भाप इंजनों का उपयोग यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पर्वतीय रेलमार्गों, मौसमी भाप से चलने वाली ट्रेनों और आईसीआरटीसी के सहयोग से किराए पर ली गई रेलगाड़ियों में किया जा रहा है। इनका उपयोग विरासत महत्व वाले रेलवे मार्गों पर किया जाता है।

भारतीय रेल ने कार्यनीतिक विद्युत खरीद योजना के आधार पर सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संयोजन से कर्षण (ट्रैक्शन) प्रयोजन के लिए अपनी विद्युत शक्ति की आवश्यकता प्रगतिशील तरीके से पूरी करने की योजना बनाई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

नवंबर 2025 तक, लगभग 812 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र और लगभग 93 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र कमीशन हो चुके हैं, जो भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चौबीसों घंटे (आरटीसी) मोड के तहत प्राप्त 100 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का प्रवाह भी ट्रैक्शन प्रयोजन के लिए आरंभ हो चुका है।

इसके अतिरिक्त, ट्रैक्शन पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरटीसी मोड के तहत 1,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को भी शामिल किया गया है।

मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों से टिकट आरक्षण प्रणाली की गई और दुरूस्त

भारतीय रेल ने मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों से टिकट आरक्षण प्रणाली को और भी दुरूस्त किया

जनवरी 2025 से अब तक 3.02 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी निष्क्रिय; प्रामाणिक टिकट बुकिंग के लिए एंटी-बॉट उपाय लागू

ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए 322 रेलगाड़ियों और आरक्षण काउंटरों पर 211 रेलगाड़ियों में आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन लागू

96 लोकप्रिय रेलगाड़ियों में से 95 प्रतिशत रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट की उपलब्धता का समय बढ़ाया गया

(जीएनएस)।

भारतीय रेल की आरक्षण टिकट बुकिंग प्रणाली एक मजबूत और अत्यधिक सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म है जो उद्योग-मानक और अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा नियंत्रणों से सुसज्जित है। भारतीय रेल ने आरक्षण प्रणाली के प्रदर्शन और नियमित/तत्काल टिकटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. उपयोगकर्ता खातों का कड़ा पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन किया गया है। जनवरी 2025 से अब तक लगभग 3.02 करोड़ संदिग्ध उपयोगकर्ता आईडी निष्क्रिय कर दी गई हैं।

2. अकामाई जैसे एंटी-बॉट समाधानों को फर्जी उपयोगकर्ताओं को हटाने और वैध यात्रियों के लिए सुचारू बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

3. तत्काल बुकिंग में दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग हेतु आधार आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। 4 दिसंबर 2025 तक यह सुविधा 322 रेलगाड़ियों में पहले से ही मिल रही है। उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त 322 रेलगाड़ियों में से लगभग 65 प्रतिशत रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट की उपलब्धता का समय बढ़ गया है।

4. आरक्षण काउंटरों पर तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी को भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है और 04.12.2025 तक इसे 211 रेलगाड़ियों में लागू किया गया है।

5. इन और अन्य उपायों के परिणामस्वरूप, 96 लोकप्रिय रेलगाड़ियों में से लगभग 95 प्रतिशत रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट की उपलब्धता का समय बढ़ गया है।

6. संदिग्ध रूप से बुक किए गए पीएनआर के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायतें दर्ज की गई हैं।

7. साइबर खतरों से सिस्टम की सुरक्षा के लिए नेटवर्क फायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणाली, एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल जैसी कई सुरक्षात्मक परतों का उपयोग किया गया है। यह सिस्टम एक समर्पित, एक्सेस-नियंत्रित डेटा सेंटर में लगाया गया है, जो सीसीटीवी निगरानी और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित है। डेटा सेंटर आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) मानकों के अंतर्गत प्रमाणित है।

साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व्यापक साइबर खतरा खुफि या सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें टेक-डाउन सेवाएं, खतरा निगरानी, डीप और डार्क वेब निगरानी और डिजिटल जोखिम सुरक्षा शामिल हैं। ये सेवाएं उभरते साइबर खतरों के बारे में सक्रिय और कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करती हैं और बेहतर घटना प्रतिक्रिया को संभव बनाती हैं।

8. आरक्षण प्रणाली की नियमित सुरक्षा जांच सीईआरटी-इन सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा एजेंसियां करती हैं। इसके अतिरिक्त, साइबर हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए सीईआरटी-इन और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) टिकट प्रणाली से संबंधित इंटरनेट यातायात की निरंतर निगरानी करती है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों/संगठनों/रेल उपयोगकताओं आदि से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अनुरोध/सुझाव/प्रतिनिधित्व प्राप्त होते रहते हैं। चूंकि ऐसे अनुरोध/सुझाव/प्रतिनिधित्व की प्राप्ति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए इनका कोई केंद्रीकृत संकलन नहीं रखा जाता है। हालांकि, इनकी समय-समय पर जांच की जाती है और व्यवहार्य एवं उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है।

यह जानकारी रेल. सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

'हाइड्रोजन से चलने वाला यात्री पोत गंगा में रवाना हुआ, जो मोदी सरकार के नेतृत्व में नेट-जीरो जलमार्गों की दिशा में एक बड़ा कदम है' - सरबानंदा सोनोवाल

■ भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का वाराणसी में वाणिज्यिक सेवा शुरू; सरबानंदा सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

■ देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरान जहाज शून्य उत्सर्जन वाला, स्वदेशी 24 मीटर लंबा स्वच्छ प्रणोदन वाला पोत है, जिसमें 50 सीटों की क्षमता है

(जीएनएस)।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने वाराणसी के नमो घाट पर देश के पहले पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत के वाणिज्यिक संचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह भारत ने अपने हरित समुद्री प्रयासों में एक बड़ा कदम उठाया है।

यह पोत भारत में समुद्री परिवेश में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणोदन का प्रदर्शन करने वाला पहला पोत है। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। यह एक निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल प्रणाली पर संचालित होता है जो संग्रहित हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करता है और उप-उत्पाद के रूप में केवल पानी उत्सर्जित करता है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत स्वच्छ, सतत और आत्मनिर्भर परिवहन प्रणालियों की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव देख रहा है। हमारे पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' की प्रतिबद्धता और सभी क्षेत्रों में हरित गतिशीलता की ओर प्रगति का एक शानदार उदाहरण है। यह उपलब्धि हमारी पवित्र गंगा के पुनरुद्धार और संरक्षण के व्यापक मिशन को भी मजबूत करती है। जैसे-जैसे हम अपने जलमार्गों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम न केवल नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास पारिस्थितिक जिम्मेदारी के साथ-साथ चले। आज की उपलब्धि हमारे राष्ट्र के लिए एक हरित और अधिक समृद्ध समुद्री भविष्य के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के अटूट संकल्प को दशार्ती है ।

भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाला यह पोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। परीक्षण संचालन पूरा होने के बाद पोत सेवा में सम्मलित हुआ। यह कदम वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और भारत के अंतदेर्शीय जलमार्गों में स्वच्छ, सतत ईंधन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों का समर्थन करता है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत की वाणिज्यिक सेवा की शुरूआत भारत के स्वच्छ और अधिक टिकाऊ समुद्री इकोसिस्टम के निर्माण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री सोनोवाल के नेतृत्व में, भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण समुद्री भारत विजन 2030 और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अंतर्गत उन्नत हरित प्रौद्योगिकियों और वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है।

सरबानंदा सोनोवाल ने कहा कि इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत की सफल तैनाती स्वच्छ और सतत जलमार्गों की ओर भारत के परिवर्तन को गति देने के लिए हमारे मंत्रालय की गहरी प्रतिबद्धता को दशार्ती है । मैं इस अग्रणी पोत की डिलीवरी के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और कठोर परीक्षणों के बाद इसे वाणिज्यिक सेवा में शामिल करने के लिए भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण को बधाई देता हूं। यह उपलब्धि वर्ष 2070 तक भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा करने और अंतदेर्शीय जल परिवहन क्षेत्र में अत्याधुनिक हरित प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के हमारे संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परिवर्तनकारी समुद्री भारत विजन (एमआईवी) 2030 और समुद्री अमृत काल विजन (एमएकेवी) 2047 के दीर्घकालिक रोडमैप के मार्गदर्शन में , हम देश के लिए एक आधुनिक, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार समुद्री इकोसिस्टम को निरंतर आकार दे रहे हैं। शहरी परिवहन के लिए डिजाइन की गई 24 मीटर लंबी कैटामरान नाव, वातानुकूलित केबिन में 50 यात्रियों को ले जा सकती है और 6.5 समुद्री मील की गति से चलती है। इसकी हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली में हाइड्रोजन ईंधन सेल, बैटरी और सौर ऊर्जा का संयोजन है, जिससे एक बार हाइड्रोजन भरने पर यह आठ घंटे तक चल सकती है। यह पोत भारतीय जहाजरानी रजिस्टर द्वारा प्रमाणित है।

पायलट पोत एफसीवी पायलट-01 को चालू करने के लिए, भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड ने तकनीकी सहायता, संचालन और निगरानी को रेखांकित करते हुए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इस समझौते में वित्तीय शर्तें, सुरक्षा प्रक्रियाएं, निगरानी तंत्र और पायलट चरण के दौरान आवधिक निरीक्षण के प्रावधान शामिल हैं।

वाराणसी में शुरू की गई हाइड्रोजन ईंधन सेल वाली नौका शहरी जल परिवहन को कई महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाती है, जिनमें यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए शोर-मुक्त यात्रा, केवल जल उत्सर्जन के साथ शून्य धुआं और शून्य प्रदूषण, और जलमार्गों के माध्यम से तेज आवागमन से सड़क पर भीड़भाड़ में कमी शामिल है। इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही वाराणसी हाइड्रोजन-संचालित यात्री परिवहन को अपनाने वाले विश्व के पहले शहरों में से एक बन जाएगा । तकनीकी रूप से, पूरी तरह से वातानुकूलित 50 सीटों वाली यह नौका संग्रहित हाइड्रोजन पर आठ घंटे तक चल सकती है, 7 से 9 समुद्री मील की गति से चलती है, और पूरी तरह से स्वदेशी, पर्यावरण के अनुकूल तकनीक द्वारा संचालित है जो सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करती है।

लखनऊ क्षेत्र के जोन 2 मे अवैध होटल बिल्डिंग का निर्माण

(जीएनएस)।

लखनऊ। थाना आशियाना क्षेत्र के अंतर्गत जोन 2 मे आशियाना सेक्टर ऊ वाला रास्ता है जोकि डिवाइडर रोड है उसी रास्ते पर बाएं हाथफैमिली बाजार के सामने चल रहा है बेसमेंट के साथ अवैध कामर्शियल बिल्डिंग का निर्माण, बिना छऊ्र के नक्शा पास करवाए, बनाई जा रही है ये होटल के लिए बिल्डिंग आप को बताते चलें लखनऊ विकास प्राधिकरण को ठेंगा दिखाते जोन 2 के दबंग बिल्डर ठेकेदार और अधिकारी, मानक को ताक पर रखकर चल रहा है ये अवैध बिल्डिंग का निर्माण जो की मानक के विपरीत है और बिना कम्पाउंडिंग फीस जमा किये बिना

सेटबैक छोड़े हुए बनाई जा रही है ये अवैध कामर्शियल बिल्डिंग गहरे बेसमेंट के साथ, काफी जोरी शोरो से चल रहा है ये अवैध बिल्डिंग का निर्माण होटल बनाने का कार्य, देखने मे ऐसा लगता है मानो की जैसे एलडीए अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा हो काम यहाँ के जेई विपिन बिहारी राय है जिनके संरक्षण मे ये अवैध निर्माण का कार्य चल रहा है और काम को चलते लगभग 8 महीना हो चुका है 5 माला तैयार भी हो चुका है, गहरे बेसमेंट के साथ क्या अभी तक किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी है इस अवैध निर्माण पर क्या निर्माण पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और अध्यसित हो जाएगा उसके बाद करेंगे कार्यवाही। एलडीए जोन-2 के उच्च अधिकारी इसको संज्ञान मे लेकर इस निर्माण पर जल्द करें कार्यवाही। या ऐसे ही फलता फूलता रहेगा अवैध कमर्शियल निर्माण।

पीलीभीतः कुनाल सिंह हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार–रमपुरा के सुरेंद्र उर्फ मुन्ना व संजय सिंह उर्फ संजू दबोचे, लाइसेंसी राइफल व कारतूस जब्त

(जीएनएस)।

बीसलपुर कोतवाली पुलिस ने कुनाल सिंह हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की पहचान रम्पुरा नगरिया निवासी सुरेंद्र उर्फ मुन्ना और संजय सिंह उर्फ संजू के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल और कारतूस भी बरामद किए हैं।

यह मामला 6 दिसंबर को दर्ज किया गया था। भगवंतपुर करोड़ निवासी बलराम सिंह ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके सुपौत्र कुनाल सिंह उर्फ विकास सिंह की देवहा नदी के पानी में डुबोकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुरेंद्र उर्फ मुन्ना, सुरेंद्र का भाई, संजय सिंह उर्फ संजू, अजय पाल का पुत्र और विजय सिंह ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा था।

गुरुवार को सुबह 11 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रम्पुरा मजार के पास से सुरेंद्र उर्फ मुन्ना और संजय सिंह उर्फ संजू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 0.30 बोर की एक लाइसेंसी राइफल, छह जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।बीसलपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले में वांछित अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है।

कौन हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर? क्यों हुई गिरफ्तारी, मुलायम से पंगा लेकर आए थे चर्चा में

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के पूर्व क्ढर अधिकारी अमिताभ ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मंगलवार देर रात उन्हें पुलिस ने सीतापुर के महोली बॉर्डर के पास से हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद भारी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया। 10 दिसंबर को अदालत ने उन्हें 23 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में देवरिया जेल भेज दिया।

पेशी के दौरान अमिताभ ठाकुर ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि "उनकी हत्या कराई जा सकती है"। पुलिस उन्हें मीडिया से बात करने भी नहीं दे रही थी और तुरंत कोर्ट के अंदर ले गई। यह गिरफ्तारी करीब 26 साल पुराने एक केस को लेकर हुई है, जिसमें उन पर सरकारी पद का

दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेजों के जरिए औद्योगिक प्लॉट लेने-बेचने के आरोप हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूर्व क्ढर अमिताभ ठाकुर कौन हैं और उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है?

◆ अमिताभ ठाकुर का जन्म बोकारो (झारखंड) में हुआ था। उन्होंने कानपुर आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के क्ढर अधिकारी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में बतौर अरढ हुई थी। बाद में पिथौरागढ़ समेत यूपी के कई जिलों में रढ रहे।

◆ अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर जानी-मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। 23 मार्च 2021 को गृह मंत्रालय ने उन्हें जबरन रिटायर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी आजाद अधिकार सेना बनाई, जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

◆ अमिताभ ठाकुर हमेशा विवादों में बने रहते हैं-चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, अखिलेश यादव की या वर्तमान योगी सरकार। वे लगातार सत्ता के खिलाफ मुखर होकर बयान देते रहे हैं।

◆2015 का वह मामला आज भी सुर्खियों में है, जब अमिताभ ठाकुर ने दावा किया कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन कर धमकी दी। उनका कहना था कि मुलायम सिंह ने कहा- "सुधर जाओ, नहीं तो पिछली बार से बुरा हाल करूंगा"। यह ऑडियो रिकॉर्ड होकर वायरल हुआ और फिर अमिताभ ठाकुर ने हजरतगंज थाने में मुलायम सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसके तुरंत बाद उन पर रेप का आरोप लगा और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बाद में इस केस में कई सवाल भी उठे।

थाना मड़ियांव क्षेत्र के अंतर्गत घैला पुल के पास हुआ भीषण एक्सीडेंट

(जीएनएस)।

लखनऊ। तेज आवाज के साथ ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई संफ ट्रैक्टर ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल ड्राइवर को तुरंत अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। हादसे का कारण बना ट्राली पर लदे भारी-भरकम बिजली के पोल, जिनका वजन ज्यादा होने से ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मड़ियांव इंस्पेक्टर को सूचना दी पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुँचकर हादसे की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों में दहशत सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी भारी लोडिंग के बावजूद सुरक्षा मानकों को क्यों नजरअंदाज किया गया?

इन किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान की 22वीं किस्त के पैसे, अभी निपटाएं ये जरूरी काम

(जीएनएस)।

देश में केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना होता है। किसी भी योजना को शुरू करने से पहले सरकार यह तय करती है कि इससे कौन-कौन लोग जुड़ सकेंगे, किन पात्रताओं की जरूरत होगी और लाभ किस तरह दिया जाएगा।

इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (ढट-ङक्रअठ), जिसके तहत करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि देश के करोड़ों किसानों को हर साल सीधे उनके बैंक खाते में तीन किस्तों के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है।

कौन-कौन किसान ले रहे हैं योजना का लाभ

पीएम किसान योजना में किसानों को साल में तीन बार 2,000 रुपये की

किस्त दी जाती है। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। यह योजना सीधे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है और पात्र किसानों को ही इसका लाभ मिलता है।

गलत दस्तावेज से आवेदन करने पर लाभ नहीं

योजना में सिर्फ वही किसान किस्त के हकदार हैं जो सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी या गलत दस्तावेज देकर आवेदन कर देता है, तो विभाग जांच के दौरान उसकी पहचान कर लेता है। इसके बाद ऐसे आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं और किसान को किस्त का लाभ नहीं मिलता। विभाग समय-समय पर ऐसे मामलों की जांच करता रहता है।

भू-सत्यापन करवाना जरूरी

पात्र किसानों के लिए भी कुछ जरूरी काम तय किए गए हैं, जिन्हें समय पर करवाना जरूरी है। इनमें सबसे अहम है भू-सत्यापन (छंल्ल्ि शेश्च्रूि३्रङ्मल्ल)। इसमें किसान की खेती योग्य भूमि की जांच की जाती है और रिकॉर्ड अपडेट किए जाते हैं। यदि किसान यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनकी किस्त रुक सकती है।

ई-केवाईसी न करवाने पर किस्त रुक जाएगी

योजना का एक और महत्वपूर्ण नियम है ई-केवाईसी कराना। यह प्रक्रिया किसान की पहचान की पुष्टि करती है और यह योजना की सबसे जरूरी शर्तों में से एक है। किसान ई-केवाईसी दो तरीकों से करा सकते हैं-

नजदीकी उरउ केंद्र पर जाकर

योजना की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए

अगर किसान ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाते, तो अगली किस्त उनके खाते में नहीं आएगी।

22वीं किस्त कब आ सकती है?

पिछली किस्तों के आधार पर देखा

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री भूतों पर करेंगे पीएचडी, कितने पढ़ें-लिखे हैं, क्या इस विषय पर होती है पढ़ाई

(जीएनएस)।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी चमत् कारिक शक्ति के लिए भक् तों के बीच लोकप्रिय हैं। हनुमान भगवान से सीधा सिंग्लन लगाकर लोगों के बारे में समस्याओं और पीड़ा को स्वयं से पता लगा लेने वाले पंडित धीरेंद्र शास् त्री ने हालिया इंटरव् यू में बड़ा खुलासा किया है।

देश- विदेश में प्रसिद्ध कथावाचक शास्त्री ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि वो पीएचडी करना चाहते हैं। हालांकि डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए जो उन्होंने विषय चुना है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतना ही नहीं ये ऐसा विषय है जिस पर पीएचडी करने की सोच कर भी आम इंसान को पसीने छूट जाएंगे।

दरअसल, एबीपी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "मैं पीएचडी करना चाहता हूं

शोध विषय के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, "सब्जेक्ट खतरनाक है... सब्जेक्ट हम भूतों पर कर रहे हैं।" इस रहस्यमयी विषय पर उनकी इच्छा ने काफी ध्यान आकर्षित किया है।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं एडमीशन

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि भूतों पर पीएचडी कई विद्वानों ने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी भूतों पर एक विषय उपलब्ध है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यद्यपि वे इस विषय पर शोध करने का विचार कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया है। उन्होंने यह भी जोड़ा, "कुछ समय बाद बाहर की यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई जरूर करूंगा।"

कितने पढ़ें-लिखे हैं पंडित धीरेंद्र शास् त्री?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धीरेंद्र शास्त्री ने अपने गाँव छतरपुर, मध्य प्रदेश के गढ़ा/गंज इलाके के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। अपनी कथाओं में बार-बार स् वयं को अंग्रेजी में कमजोर बताने वाले पंडित शास् त्री के पढ़ाई के बारे में अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में 8वीं पास तो किसी में 12 पास होने का दावा किया गया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जाता है इन्होंने बीए की डिग्री भी हासिल की है।

क्या सच में भूत विषय पर पीएचडी संभव है?

अब आपके दिमाग में ये सवालआना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में विश्वविद्यालय वास्तव में भूतों के अध्ययन से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। एडिनबरा विश्वविद्यालय पिछले 50 वर्षों से इस तरह का एक कोर्स चला रहा है। थॉमस फ्रांसिस यूनिवर्सिटी भी ऐसे विषयों हैं, जहाँ छात्र अलौकिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं।

'विदेश जाकर गलत काम करते हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी,' रिवाबा जडेजा के खुलासे से क्रिकेट जगत में हड़कंप

(जीएनएस)।

रवींद्र जडेजा की पत्नी और गुजरात सरकार में मंत्री रिवाबा जडेजा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने क्रिकेट जगत में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सीधे तौर पर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की संस्कृति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

अपने पति की तारीफ करते हुए, रिवाबा जडेजा ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके पति, रवींद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन और दुबई जैसे अनेकों देशों में खेलने जाते हैं, फिर भी आज दिन तक उन्होंने कभी किसी तरह का व्यसन (नशा) नहीं किया है। इसके ठीक विपरीत, उन्होंने टीम के बाकी खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए कहा कि टीम के बाकी सारे खिलाड़ी विदेश जाकर गलत काम करते हैं और गलत आदतों में पड़ते हैं।

रिवाबा जडेजा ने इस बात पर जोर दिया कि जडेजा के पास पूरी आजादी है और वह चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी जवाबदेही और अनुशासन को समझते हुए इन चीजों से दूर रहते हैं। उनका यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से टीम के अन्य खिलाड़ियों पर अनुशासनहीनता और अनैतिक आचरण का आरोप लगाता है।

पटियाला में सड़क निर्माण में मिली अनियमितताएं, सीएम भगवंत मान ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर भुगतान रोका

(जीएनएस)।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को पटियाला जिले में रीटखेड़ी लिंक रोड के निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने के बाद संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसके भुगतान रोकने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने निमार्णाधीन सड़क का औचक निरीक्षण किया था और सड़क के नमूनों की जांच के बाद निर्धारित वजन मानदंडों का पालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की।

मुख्यमंत्री मान ने अधिकारियों को ठेकेदार को तत्काल नोटिस जारी करने और उसके सभी भुगतान रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने पटियाला जिले में निमार्णाधीन पटियाला-सरहिंद रोड का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को सड़क के नमूनों को प्रयोगशाला से जांच करवाने को कहा। इसके अलावा, उन्होंने फतेहगढ़ साहिब जिले में रुड़की से रेओना तक की सड़क परियोजना का भी जायजा लिया।

भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि इन निमार्णाधीन सड़कों की जांच का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में बन रही सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सड़कों के निर्माण पर बड़ी राशि खर्च कर रही है; इसलिए यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह आने वाले दिनों में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रखेंगे, क्योंकि सार्वजनिक धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह औचक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके और सर्वोत्तम सामग्री के साथ सड़कों का उचित निर्माण हो। उन्होंने संबंधित विभागों को उचित समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि सीवरेज लाइन, पेयजल पाइप, फाइबर और अन्य सभी कार्य सड़क निर्माण से पहले ही पूरे कर लिए जाएं। मान ने कहा कि इससे नई बनी सड़कों को कम से कम नुकसान होगा और सार्वजनिक धन का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने लोगों से भावुक अपील करते हुए उनसे सड़क निर्माण कार्यों पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखने का आग्रह किया, क्योंकि ये उनकी अपनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि आम जनता को इन कार्यों की देखरेख करनी चाहिए और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर राज्य सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। मान ने आश्वासन दिया कि दोषी ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बालाघाट में तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 राजकुमार रामटेके 3,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की सख्ती रंग ला रही है। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश पर जबलपुर लोकायुक्त इकाई ने बालाघाट जिले के तहसील बिरसा कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 राजकुमार रामटेके (58 वर्ष) को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

आरोपी ने आवेदक संतोष डेकवार से उनके खिलाफ चल रहे प्रकरण (धारा 126, 135(3) इठरर) को खत्म करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। ट्रैप आज (11 दिसंबर 2025) मलाजखंड सालीटेकरी मेन रोड पर प्रशांत फोटोकॉपी के पास सफल हुई।

आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 13(1)इ और 13(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह 2025 में जबलपुर लोकायुक्त की कई सफल ट्रैप्स में से एक है, जो राजस्व और तहसील कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर कर रही है।

ट्रैप का पूरा घटनाक्रमः शिकायत से सड़क पर गिरफ्तारी तक

आवेदक संतोष डेकवार (पिता स्व. चमारुलाल, निवासी वार्ड नंबर 7, पौनी मलाजखंड, बालाघाट) के

खिलाफ नायब तहसीलदार कार्यालय बिरसा में धारा 126, 135(3) इठरर का प्रकरण चल रहा था।

रिश्वत की मांगः सहायक ग्रेड-3 राजकुमार रामटेके ने प्रकरण खत्म करने के लिए 3,000 रुपये मांगे।

शिकायतः संतोष ने यह बात पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को बताई। सत्यापन में मांग सही पाई गई।

ट्रैप प्लानः आज संतोष को 3,000 रुपये देकर भेजा गया। रामटेके ने प्रशांत फोटोकॉपी के पास मेन रोड पर रिश्वत ली।

गिरफ्तारीः ट्रैप टीम ने मौके पर ही रामटेके को दबोच लिया। नोटों पर चूना-पाउडर के निशान मिले।

लोकायुक्त रढ ने कहा, "यह छोटी राशि का मामला लगता है, लेकिन तहसील स्तर पर आम नागरिकों की फाइलें अटकाकर घूस लेने की यह प्रवृत्ति गंभीर है। हमारी टीम ने सटीक प्लानिंग से ट्रैप सफल की।"

लोकायुक्त ट्रैप टीम की सराहनीय भूमिका

ट्रैप दल में शामिल रहेः

दल प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया

ट्रैप कर्ता निरीक्षक जितेंद्र यादव

जबलपुर लोकायुक्त का पूरा दल

टीम ने सड़क पर घेराबंदी की और रामटेके को रिश्वत लेते पकड़ा।

आरोपी राजकुमार रामटेकेः 58 साल का क्लर्क, घूसखोरी का पुराना तरीका

राजकुमार रामटेके (पिता स्व. खुशियाल रामटेके, उम्र 58 वर्ष) तहसील बिरसा में सहायक ग्रेड-3 हैं। विभाग में फाइलें आगे बढ़ाने के नाम पर छोटी-छोटी रिश्वत लेने की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। जांच में उनके बैंक खातों और संपत्ति की पड़ताल होगी।

तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचारः आम नागरिक परेशान

बालाघाट जैसे आदिवासी बहुल जिलों में तहसील कार्यालयों में नामांतरण, बंटवारा और राजस्व प्रकरणों में घूसखोरी आम है। क्लर्क और रीडर फाइलें अटकाकर पैसे वसूलते हैं। संतोष जैसे आवेदक अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन डर से चुप रह जाते हैं। यह ट्रैप उन सभी के लिए राहत की खबर है।

आदिवासी क्षेत्र में सवाल

बालाघाट-झाबुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। विभाग में भ्रष्टाचार का यह मामला विपक्ष के लिए हथियार बनेगा। कांग्रेस ने कहा, "मोहन सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर।" इखढ ने कहा, "लोकायुक्त स्वतंत्र है, कार्रवाई हो रही है।"

छोटी रिश्वत, बड़ा संदेश

3,000 रुपये की यह रिश्वत छोटी लगती है, लेकिन यह तहसील स्तर के भ्रष्टाचार की बड़ी तस्वीर है। लोकायुक्त की यह कार्रवाई अन्य क्लर्कों के लिए चेतावनी है। क्या जांच में और खुलासे होंगे? वनइंडिया हिंदी अपडेट लाता रहेगा।